भारत सरकार

संसदीय कार्य मंत्रालय

***

7 मई, 2019

प्रेस विज्ञप्ति

डिजिटलीकरण के युग में, संसदीय कार्य मंत्रालय नेशनल ई-विधान एप्लिकेशन, एक मिशन मोड परियोजना, जो भारत सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का हिस्सा है, के माध्यम से विधानमंडलों के कामकाज को कागज रहित बनाने जा रहा है। मंत्रालय संसद के दो सदनों सहित विधानमंडलों के 40 सदनों को शामिल करते हुए राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (नेवा) को लागू करने के लिए भरपूर प्रयास कर रहा है।

इस दिशा में, संसदीय कार्य मंत्रालय ने वेब के साथ-साथ मोबाइल एप्लिकेशन "नेशनल ई-विधान एप्लिकेशन" को विकसित किया है। नेवा का उद्देश्य विधानमंडलों के सदस्यों की विधायी चर्चाओं और कानून बनाने की प्रक्रिया में भागीदारी हेतु खुद को तैयार करने के लिए नवीनतम आई.सी.टी. उपकरणों का उपयोग करने में मदद करना है। इस परियोजना में सचिवालयों की सभी शाखाओं का कम्प्यूटरीकरण, पहचान की गई सेवाओं की कार्य प्रक्रिया री-इंजीनियरिंग, क्षमता निर्माण और विधानमंडलों के सदस्यों और सरकारी विभागों के संबंधित अधिकारियों तथा अन्य अधिकारियों का प्रशिक्षण, सदस्यों की सहायता के लिए ई-सुविधा केंद्रों की स्थापना, सार्वजनिक पोर्टलों के माध्यम से सार्वजनिक सेवाओं का परिदान शामिल है।

नेवा एक सदस्य-केंद्रित एप्लिकेशन है जो मोबाइल सहित ऑनलाइन प्रश्न और अन्य नोटिस प्रस्तुत करने के लिए सदन के प्रत्येक सदस्य हेतु एक सुरक्षित पेज के साथ-साथ कार्यसूची, नोटिस, समाचार-1, समाचार-2, मंत्रालयों/विभागों द्वारा उत्तर सहित तारांकित/अतारांकित प्रश्नों, पुर:स्थापन/विचारण और पारण के लिए विधेयकों, कार्यवाहियों के सारांश, सदन की शब्दश: कार्यवाहियों, समिति की रिपोर्टों, प्रक्रिया नियमों, डिजिटल पुस्तकालय, अस्थायी कलैंडर, संदर्भ सामग्री, मंत्रालयों के रोटेशन, संपर्क, बजट, प्रेस विज्ञप्तियों को शामिल करते हुए सदनों के दिन-प्रतिदिन के कार्यचालन का समाधान करती है।

दिनांक 07.05.2019 को पूर्वाह्न 11 बजे सरदार वल्लभभाई पटेल हॉल, उपराष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली में सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा श्री एम. वैंकैया नायडु, भारत के उप-राष्ट्रपति और राज्य सभा के सभापति के समक्ष राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन पर एक प्रस्तुति दी गई।

सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय ने स्पष्ट रूप से नेवा की प्रमुख विशेषताओं के साथ-साथ इसकी पृष्ठभूमि, विस्तार और उद्देश्यों के बारे में बताया जो इसे डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत भारत सरकार द्वारा संचालित विभिन्न अन्य परियोजनाओं से अलग बनाते हैं। सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय ने वेब एप्लिकेशन और मोबाइल एप्लिकेशन के उद्देश्यों, खूबियों, कार्य योजना और डिजाइन का विस्तृत विवरण दिया। उन्होंने इस एप्लिकेशन को अपनाने के पीछे जो मुख्य विचार है उस पर भी जोर दिया जो इसे आज तक विकसित विभिन्न एप्लिकेशनों से बेहतर बनाता है। प्रतिभागियों को बताया गया कि सूचना का

डिजिटलीकरण, उपलब्धता और प्रयोज्यता से सदनों और उसके सदस्यों के कीमती समय, धन, ऊर्जा और संसाधनों की बचत होती है और इस प्रकार उनकी क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। उन्होंने इस तथ्य को दोहराया कि सदस्यों की सेवा करने के लिए एप्लिकेशन का केंद्रीय उद्देश्य उतना ही सार्थक साबित होगा, जितना कि लोकतंत्र को मजबूत करना है। नेवा सदन प्रबंधन एप्लिकेशनों के माध्यम से सदन के प्रबंधन में अध्यक्ष की भी मदद करेगा। इस अकेली एप्लिकेशन को इस तरह से डिजाइन किया गया है जिसमें वर्तमान में राज्य सभा सचिवालय की वर्तमान एप्लिकेशनों का स्थान लेने की क्षमता है, जिसके लिए दोनों सदनों से सामूहिक और सहयोगात्मक प्रयास की अपेक्षा की जाती है। सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय ने संसदीय प्रक्रियाओं में पेश आ रहे मुद्दों का समाधान करने और इसे एक सफल परियोजना बनाने के लिए नेवा टीम के साथ दोनों सदनों की सामूहिक भागीदारी की वकालत की।

यह एप्लिकेशन विधानमंडलों के साथ-साथ सरकारी विभागों द्वारा उपयोग के लिए उपलब्ध है। उप-राष्ट्रपति सचिवालय और राज्य सभा सचिवालय के 20 से अधिक अधिकारियों ने प्रस्तुति में भाग लिया। भारत के उप-राष्ट्रपति और सभापति, राज्य सभा ने नेवा एप्लिकेशन के विकास के माध्यम से विधानमंडलों का डिजिटलीकरण करने की दिशा में संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा की गई पहल और प्रयासों की सराहना की और राज्य सभा सचिवालय के अधिकारियों को राज्य सभा के कामकाज में नेवा का उपयोग करने की संभावनाओं का पता लगाने का निर्देश दिया। अध्यक्ष महोदय का विचार था कि दोनों सदन नेवा की छानबीन करने के लिए एक साथ बैठें और अपनी अतिरिक्त अपेक्षा, यदि कोई हो, के बारे में संसदीय कार्य मंत्रालय को, नेवा को तदनुसार अनुरूपित करने के लिए बताएं। बैठक अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देते हुए समाप्त हुई।

****